कर दिया है और प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना को शीघ्र चालू करवाने के संबंध में क्या प्रयास किए है और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (घ) नर्मदा नदी के जल के बंटवारे के बारे में मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच विवाद के कारण नर्मदा जल विवाद अधिकरण नियुक्त किया गया था। तदनन्तर राजस्थान को भी एक पक्ष के रूप में शामिल कर दिया गया था। इस अधिकरण ने नदी में उपयोज्य जल प्रवाह की कुल उपलब्धता का मूल्यांकन किया तथा उसे भागीदार राज्यों को आबंटित किया। अधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि 138.7 एम के एफ०आर०एल० सहित सरदार सरोवार परियोजना को एक अन्तर्राज्यीय परियोजना के रूप में तथा एफ०आर०एल० 262 एम सहित मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिकरण ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण तथा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के गठन के लिए भी निर्देश दिए थे। भारत सरकार द्वारा इन संगठनों का गठन पहले ही किया जा चुका है ।

विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नर्मदा सागर परियोजना के लिए सहायता के लिए भी विश्व बैंक के साथ विचार किया जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना तथा नर्मदा सागर परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त होने की प्रतीक्षा है ।

USSR technology for metallurgy units

1728. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:
SHRI SUBAS MOHANTY:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Governments attention had been drawn to the news item published in the 'Statesman' dated the 14th October, 1986 to the effect that USSR had offered their latest technology for metallurgy units, if so, what are the details thereof;

(b) whether this is the best technology available in the world; and

(c) whether our own Research and Development units on which heavy recurring and non-recurring expenditure is being made have contributed to any new development which is not already known overseas and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) Yes, Sir. Both sides are already cooperating and have jointly identified schemes to remove any bottlenecks and to improve the technical and economic indices and the quality of products at the Bhilai and Bokaro Steel Plants.

(b) The technologies that are being supplied by the Soviet Union have been found to be appropriate for application in these plants.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Drug abuse in the country

1729. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether fast developing drug abuse in the country is leading to social concern and also law and order problems as reported in the 'Hindustan Times' of the 15th October, 1986; and

(b) whether the siutation has been examined and analysed by Government, if so, the results thereof and action proposed in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) Results of any such surveys are not available. However, the Government have adopted an integrated approach and policy and taken a number of legal, welfare and awareness building measures to counteract the problem of drug abuse.

Drought in Uttar Pradesh

1730. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment of the damage to the Kharif crop as a result of severe drought in many districts of Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh have requested for Central assistance to the tune of rupees 470 crores for fighting drought situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) In their memorandum seeking Central assistance for expenditure of Rs. 474.82 crores for tackling drought in some parts of the State, the Government of Uttar Pradesh have reported that 72 lakh hectares of cropped area has been affected by drought. A Central Team has already visited the State for making an assessment of the situation.

दूध की मांग

1731. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनसंख्या के हिसाब से दूध की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) देश में अनुमानत: कितना दूध उपलब्ध है ;

(ग) यदि दूध की कोई कमी है तो इसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) दूध तैयार करने के लिए विदेशों से नि:शुल्क मिलने वाला 15 करोड़ रुपए मूल्य का दुग्ध चूर्ण तथा नि:शुल्क बटर आयल कब तक मिलता रहेगा और उस अवधि के पश्चात् सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट (1976) के अनुसार वर्ष 1985 में दूध के मांग-प्रक्षेपण का उच्च और निम्न स्तर क्रमश: 442 और 334 लाख मीटरी टन है। अत: वर्ष 1985 की औसत मांग 388 लाख मीटरी टन मानी जा सकती है।

(ख) 1985-86 के दौरान देश में प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन 423 लाख मीटरी टन है।

(ग) दूध की मांग को मुख्यत: पूरा कर लिया गया है। फिर भी सरकार ने आपरेशन फ्लड परियोजना सहित केन्द्रीय, केन्द्रीय प्रायोजित और राज्य की प्लान स्कीमों के जरिए देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनेक उपाय किये हैं। ये उपाय हैं :— अनजानी नस्ल के गो-पशुओं का डेरी की विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन और देशी गो-पशुओं और भैंसों के चुनींदा प्रजनन के जरिए दुग्ध उत्पादन की क्षमता में सुधार करना, संक्रामक रोगों के नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य के पर्याप्त प्रबंध, आहार/चारे के संसाधनों के विकास के माध्यम से पोषक तत्वों में सुधार करना और दुग्ध विपणन की सुनिश्चित सुविधाओं का सृजन करना।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के खाद्य-सहायता कार्यक्रम 1985 से आगे आपरेशन फ्लड चरण 3 के लिये दुग्ध चूर्ण की सप्लाई करने के लिये अभी तक कोई ठोस वादा नहीं किया है। तथापि भविष्य में स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल/बटर का आयात करनें के बारे में सरकार की नीति इस संबंध में प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।